

**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** नेपा में यह जो अखबारी कागज़ तैयार होता है, क्या यह सत्य है कि उस को कुछ समय के बाद कच्चा माल मिलने में बड़ी कठिनाई हो जायगी, यदि हां, तो उस की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

**Shri Bibudhendra Misra:** No, Sir; because, as a matter of fact, the capacity is being expanded from 30,000 tons per year to 75,000 tons.

**Shri A. S. Saigal:** May I know whether it is a fact that the grievance of the Language Newspapers' Association is long-standing and how long will it take for the Government to solve it?

**Shri Bibudhendra Misra:** The grievance of language newspapers does not come in here at all.

**श्री म० ला० द्विवेदी :** नेपा मिल का जो न्यूज़प्रिंट है, क्या यह सच नहीं है कि वह उस क्वालिटी का नहीं होता है जिस अच्छी क्वालिटी का विदेशों में आता है ? यदि हां, तो इस का क्या कारण है ? इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, जो कंज्यूमर्स की शिकायतें हैं, उन को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कोई कदम उठाये हैं और यदि नहीं उठाये हैं, तो क्या वे उठाये जा रहे हैं ?

**Shri Bibudhendra Misra:** The quality is bound to be inferior because the imported paper is made from soft woods which are not available in India.

**श्री य० सि० चौधरी :** अखबारी कागज़ की कमी को देखते हुए क्या सरकार इस बात का विचार कर रही है कि नेपा की फैक्ट्री के अन्दर एक और यूनिट काम करे अगले साल के अन्दर जिस से कमी पूरी हो सके ?

**Mr. Speaker:** It is a suggestion for action.

**Shri Kapur Singh:** What steps, if any, are Government taking or propose to take to discover a commercially feasible dechromatising agent to bleach out the yellow strain in the Silai wood pulp used in the manufacture of Nepa newsprint?

**The Minister of Heavy Engineering in the Ministry of Industry and Supply (Shri T. N. Singh):** That is a technical question involving technical considerations. Full bleaching of the Salai wood pulp is difficult.

**Shri Kapur Singh:** Are any steps being taken to discover any scientific agent such as I mentioned?

**Mr. Speaker:** That is too wide a question.

**Shri Kapur Singh:** That is the only grievance which the newspapers have against Nepa newsprint.

#### Textile Control Orders

+

{ **Shrimati Savitri Nigam:**  
**Shri N. P. Yadab:**  
 \*401. { **Shri Yashpal Singh:**  
**Shri Indrajit Gupta:**  
**Shri Kapur Singh:**

Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) whether it is a fact that textile control orders have not been strictly enforced in various States;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action being taken to see that control orders are enforced properly?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri S. V. Ramaswamy):** (a) to (c). Presumably the Hon'ble Members refer to Voluntary Price Control Scheme on cotton cloth. As the scheme was not giving full satisfaction, it is proposed to bring in statutory production and price control on certain categories of cloth of popular mass consumption.

**Shrimati Savitri Nigam:** May I know whether the Minister is aware that there is a lot of profiteering going on even in the coarse cloth and the price charged is much more than what is printed on the cloth?

**Shri S. V. Ramaswamy:** I do not think there is much profiteering in coarse cloth.

**Shrimati Savitri Nigam:** How long will it take to make the new arrangement and what are the details of the new arrangement which they are going to make to control it?

**Shri S. V. Ramaswamy:** As quickly as possible, but the details cannot be disclosed at this stage.

**Shrimati Savitri Nigam:** I want to know the main features of it.

**The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah):** I will be making a statement on Monday comprehending the whole control order—both production and price control—on popular varieties.

**श्री यशपाल सिंह :** क्या सरकार बता सकती है कि अभी तक किन स्टेट्स ने इन पर अमल किया है और किन किन स्टेट्स ने नहीं किया है ? क्या इस तरह का भी कोई आंकड़ा आप के पास है कि कितने मिल मालिकान के खिलाफ एक्शन लिया गया है ?

**श्री मनुभाई शाह :** पिछली बार मैंने बताया था कि दस मिल मालिकान ने वालैटरी प्राइस कंट्रोल, जो स्टैचुटरी नहीं है, का उल्लंघन किया था। फौरन इस की तहकीकात की गई और वे फिर वालैटरी प्राइस कंट्रोल पर आ गये।

**श्री यशपाल सिंह :** कितने मिल मालिकान के खिलाफ एक्शन लिया गया है ?

**श्री मनुभाई शाह :** यही मैंने बताया है। वालैटरी प्राइस कंट्रोल है जो कानूनी नहीं था। इस बजह से जो एक्शन हम ले सकते थे वह यही हो सकता था कि फौरन उन से कहते कि जो पुराना सिस्टम था, उस पर चले जाओ और वे चले गये।

**श्री हुकम चन्द कछबाय :** केन्द्रीय सरकार द्वारा 118 करोड़ रुपये के जो टैक्स कपड़े पर लगाये गये थे, क्या यह सही नहीं है कि उन के कारण से भी हलके कपड़े की कीमतें बढ़ी हैं।

**श्री मनुभाई शाह :** जो एक्साइज ड्यूटी है वह पालियामेंट ने पास की थी। वह तो लगनी ही थी।

**अध्यक्ष महोदय :** वह तो जरूरी था।

**Shri P. Venkatasubbiah:** Under the garb of voluntary price control, many malpractices are being indulged in by putting more price than is justified by the quality of the cloth. If that is so, may I know whether all these factors will be taken into consideration in the new control order that is going to be promulgated.

**Shri S. V. Ramaswamy:** The new control order will be made only for certain popular varieties and they will be controlled in such a manner that the malpractices will be reduced and brought under control.

**Shri Kapur Singh:** In addition to price control, are Government taking any steps to facilitate the production of cheap durable people's cloth?

**Shri Manubhai Shah:** It will be all people's cloth.

**Shri Kapur Singh:** He is being not only evasive but flippant. He says it will be all people's cloth. He knows what I mean by people's cloth. People's cloth is that which is cheap and durable and which is within the means of the people.

Mr. Speaker: He says that all cloth that is being referred to satisfies the description given by the hon. Member.

Shri Kapur Singh: It wears off in the third month of its use.

Mr. Speaker: That may be a matter of argument.

श्री रामेश्वरानन्द : जो कपड़ा विदेशों को भेजा जाता है, उस के कारण भी क्या कपड़े के मूल्यों में वृद्धि हुई है ? देश की आन्तरिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार कपड़ा बाहर भेजने पर रोक लगाने का यत्न करेगी ?

श्री मनुभाई शाह : माननीय सदस्यों को पता है कि हमारे यहां कोई खेंच नहीं है। जो निर्यात किया जाता है, वह सर्पलस कपड़े में से किया जाता है। हमारा निर्यात भी बढ़ा है, अन्दर का कंजम्पशन भी बढ़ा है और उत्पादन भी बढ़ा है।

दिल्ली में यमुना पर रेलवे पुल

+

\* 402. { श्री प्रकाशबीर शास्त्री :  
श्री यशपाल सिंह :  
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में यमुना पर बना हुआ रेलवे पुल काफ़ी कमजोर हो गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारी गाड़ियों तथा अन्य वाहनों के इस पर गुजरने से यह हिलने लगता है ; और

(ग) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ज्ञान नाथ) : (क) जी नहीं। पुल की निचली

तामीर ( substructure ) या उसके गडरों में कोई खराबी नहीं पाई गई है ।

(ख) गाड़ियों आदि के गुजरते समय गडर पुल में कुछ वाइब्रेशन का होना कुदरती बात है ।

(ग) ऊपर भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए इस मामले में कोई कार्रवाई करना जरूरी नहीं है ।

श्री प्रकाशबीर शास्त्री : इस प्रकार के जो ये बड़े पुल बनते हैं, इनकी क्या कोई धातु भी निर्धारित की जाती है कि किस समय तक ये पुल काम देंगे ? यह पुल जब बना था तो क्या इसकी उम्र कोई निर्धारित की गई थी, यदि हां, तो कब तक इसका समय था ?

श्री ज्ञान नाथ : यह पुल 1867 में बना था और उसके बाद इसमें एडीशंस होती रहीं। इस वक्त जो हालत है पुल की, वह बिल्कुल ठीक है और इसकी फाउंडेशन वर्गरेह की मजबूती बिल्कुल सही है। इसमें जो वाइब्रेशंस होते हैं, वह एक कुदरती बात है। गडर पुलों में वे होते ही हैं।

जहां तक लाइफ का ताल्लुक है, ऐसी बात नहीं है कि कोई लाइफ खास मुकर्रर की जाए किसी एक पुल की ।

श्री प्रकाशबीर शास्त्री : आपने कहा है कि धातु नियत नहीं की गई, लेकिन भेरी जानकारी में वह की गई थी। दूसरी बात में यह जानना चाहता हूं कि दिल्ली भारतवर्ष की राजधानी है और इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था भा. की है कि कोई दूसरा रेलवे का पुल बना दिया जाए जिससे कभी कोई ऐसी स्थिति न आए कि यह पुल काम न दे तब तत्काल कोई कठिनाई उत्पन्न न हो ?